डॉ अमरेंद्र कुमार

जलवायु वित्त और भारत का सतत विकास

जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विकासात्मक पहलों के साथ तालमेल बनाकर काम करने वाले महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाना अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों और विवेकपूर्ण निवेश की आवश्यकता है ताकि उत्सर्जन को कम किया जा सके, पहले से महसूस किए जा रहे प्रभावों के अनुकूल ढलने को प्रोत्साहित किया जा सके और लचीलेपन को बढ़ाया जा सके।

प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य 'सुभाषित रत्नाकर' की उक्ति के अनुसार, "पृथिव्याम् त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्," (भटवडेकर) जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं– जल, अन्न और सुभाषित (अच्छे वचन)। यह उक्ति सतत विकास लक्ष्य 6 और सतत विकास लक्ष्य 2 पर ज़ोर देती है, जो क्रमशः गुणवत्तापूर्ण भोजन और पीने योग्य पानी से संबंधित हैं। ये जलवायु के दो महत्वपूर्ण रत्न हैं, जो सीधे सतत विकास लक्ष्य 13 से जुड़े हैं, जो जलवायु और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे जलवायु मुद्दों से निपटने में जलवायु वित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। (द ग्लोबल गोल्स, 2015)

जलवायु वित्त से तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के शमन, अनुकूलन या प्रतिरोधक क्षमता के लिए ऋण, अनुदान या घरेलू बजट आवंटन जैसे वित्तीय संसाधनों से है।

यह लेख जलवायु वित्त और भारत को 'विकसित' बनाने में इसकी भूमिका पर ज़ोर देगा, यानी हरित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन उपलब्ध कराकर, और देश भर में हरित म्युनिसिपल बॉन्ड, हरित बजट, हरित सकल घरेलू उत्पाद आदि जैसे विभिन्न उपायों पर भी चर्चा करेगा।

यह लेख अंतर्दृष्टि में भी उतरता है और जलवायु वित्त से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी भूमिका और दुनिया को हरा-भरा बनाने में उनके महत्व को समझने की कोशिश करता है। यह देश भर में जलवायु परिवर्तन के संबंध में किए गए विभिन्न उपायों से भी संबंधित है और वैश्विक उपायों के साथ उनकी तुलना करता है।

ईशोपनिषद के अनुसार, "प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है।", जिसका अर्थ है कि प्रकृति अपने सिद्धांतों और नियमों के साथ चलती है, जिससे पृथ्वी ग्रह पर जीवन सुचारू रूप से चलता है। और कोई भी बाहरी सम्मिश्रण उस एकमात्र ग्रह पर विनाश का कारण बन सकता है जहाँ जीवन मौजूद है।

जलवायु संबंधी मुद्दों में बढ़ता तापमान, वायु प्रदूषण, प्रजातियों का विलुप्त होना, महासागर का अम्लीकरण, प्लास्टिक कचरा संकट आदि शामिल हैं, जो मानवीय लालच और प्रकृति के साथ लापरवाही

लेखक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के वाणिज्य विभाग में सह-आचार्य हैं। ईमेलः amrendrakumar84@gmail.com

के कारण उत्पन्न हुए हैं। ग्लोबल फ़ॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया ने 2010 और 2023 के बीच 2.83 करोड़ हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो दिया है, और यह परिदृश्य को और भी बदतर बना रहा है। इन समस्याओं के कारण, यह पर्यावरणविदों, पारिस्थितिकीविदों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। व्यापार क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, और जलवायु वित्त व्यापार जगत की ओर से एक समाधान के रूप में कार्य करता है।

"जलवायु वित्त वह धन है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने (शमन) और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने (अनुकूलन) के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाओं का समर्थन करता है (इंट्रोडक्शन टू जलवायु वित्त, 2001)।" इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों निवेश शामिल हैं और यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रवाहित होता है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें ऋण, अनुदान और घरेलू बजट आवंटन जैसे विभिन्न वित्तीय संसाधन शामिल हैं।

जलवायु वित्त

"जलवायु वित्त से तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है–जो सार्वजनिक, निजी और वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त होता है–जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले शमन और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना चाहता है (इंट्रोडक्शन टू जलवायु वित्त, 2001)।"

इंट्रोडक्शन टू जलवायु वित्त, 2001 की रिपोर्ट के अनुसार, "पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन, सभी उन पक्षों से, जिनके पास अधिक वित्तीय साधन हैं–यह अपेक्षा करते हैं कि वे उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करें जो अधिक संवेदनशील और कम संपन्न हैं। यह इस बात को स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रों का योगदान, साथ ही इसे रोकने और इसके प्रभावों से निपटने की उनकी क्षमता, काफी भिन्न है। चूंकि सार्थक उत्सर्जन कटौती प्राप्त करने के लिए बड़े व्यय की आवश्यकता होती है, इसलिए शमन के लिए जलवायु वित्त आवश्यक है। चूंकि बदलती जलवायु के नकारात्मक प्रभावों के अनुकूल होने और दुष्परिणामों को कम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए अनुकूलन के लिए भी जलवायु वित्त समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह 'समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं' के सिद्धांत पर संचालित होता है, जो कहता है कि अमीर देशों को अविकसित देशों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए धन का योगदान देना चाहिए।"

"पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9 विकसित देशों के दायित्वों की पुष्टि करता है, जबकि पहली बार, अन्य पक्षों से स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करता है। विकसित देश के पक्षों को विभिन्न स्रोतों, साधनों और माध्यमों से जलवायु वित्त जुटाने में नेतृत्व करना जारी

रखना चाहिए, सार्वजनिक धन की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए कई कदम उठाने चाहिए, जैसे कि राष्ट्र-संचालित योजनाओं में सहायता करना और विकासशील देश के पक्षों की जरूरतों और लक्ष्यों को ध्यान में रखना। इस प्रकार का जलवायु वित्त जुटाना पिछली पहलों की तुलना में एक प्रगति होनी चाहिए। सामान्य तौर पर, वित्तीय प्रवाह को कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास की दिशा में संरेखित करने का पेरिस समझौते का लक्ष्य इसकी गतिविधियों के लिए एक दिशा के रूप में कार्य करता है। समझौते के वैश्विक सर्वेक्षण में सहायता जुटाने और प्रावधान की स्थिति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। पेरिस समझौता वित्तीय सहायता में बेहतर पूर्वानुमान और पारदर्शिता पर भी ज़ोर देता है (यूएनएफसीसी, 2015)।"

"प्रत्येक सरकार और हितधारक को विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताओं को समझना और मूल्यांकन करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि इन संसाधनों को कैसे जुटाया जाए। अनुकूलन और शमन के बीच संसाधनों के प्रावधान में संतुलन प्राप्त करना भी लक्ष्य होना चाहिए (यूएनएफसीसी, 2015)।"

जलवायु वित्त से संबंधित वित्तीय तंत्र और अन्य कोष

वित्तीय तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो जलवायु वित्त से संबंधित प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने और क्योटो तथा पेरिस समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है, जो विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु वित्त कोष

वैश्विक स्तर पर प्रदान की जाने वाली कुछ प्रसिद्ध नीतियां और कोष इस प्रकार हैं:

1. **वैश्विक पर्यावरण सुविधा:** 1992 में शुरू की गई, इसने कई पर्यावरणीय सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र की परिचालन इकाई के रूप में कार्य किया है।
2. **हरित जलवायु कोष:** 2010 में कैनकन में आयोजित 'कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज' द्वारा स्थापित, और यह दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष बन गया है। यह 2011 में वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई भी बन गया। यह विकासशील देशों में क्रांतिकारी जलवायु कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए लचीले वित्तपोषण विकल्पों, जलवायु निवेश ज्ञान और देश के स्वामित्व वाले साझेदारी दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
3. **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष:** विकासशील देशों के जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए 2001 में स्थापित किया गया। यह वित्तीय तंत्र के एक भाग के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा किया जाता है।
4. **अल्प विकसित देश कोष:** क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2001 में अल्प विकसित देशों के जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया। यह वित्तीय तंत्र के हिस्से के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा किया जाता है।
5. **अनुकूलन कोष:** अनुकूलन कोष एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्तपोषण प्रणाली है जिसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया था। यह कोष, जो 2007 में चालू हुआ, विकासशील देशों में विशिष्ट अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
6. **हानि और क्षति प्रतिक्रिया कोष:** 2023 में 'कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ 28' द्वारा स्थापित, जो उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सहायता करता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इसके हिस्से के रूप में, विश्व बैंक को कोष को संचालित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

वित्त पर स्थायी समिति

सम्मेलन के वित्तीय ढांचे से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने में 'कॉप' का समर्थन करने के लिए 2010 के 'कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ 16' में एक स्थायी वित्त समिति बनाई गई थी। इसका उद्देश्य सम्मेलन के भीतर और बाहर, जलवायु वित्तपोषण से जुड़े कर्ताओं और परियोजनाओं के बीच संबंधों को मज़बूत करना और सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

दीर्घकालिक जलवायु वित्त

इसका उद्देश्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, सार्वजनिक और निजी, साथ ही गैर-पारंपरिक स्रोतों सहित विभिन्न स्रोतों से जलवायु वित्त जुटाने और उसे बढ़ाने की सुविधा प्रदान करना है। जलवायु वित्त के लिए एक निश्चित राशि आवंटित की जाती है।

राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु वित्तपोषण कोष और विकसित भारत@2047 का दृष्टिकोण

भारत सरकार का लक्ष्य, जिसे 'विकसित भारत' के रूप में जाना जाता है, 2047 तक, यानी अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक, भारत को एक विकसित देश में बदलना है। इस दृष्टिकोण में सामाजिक उन्नति, आर्थिक विस्तार, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन जैसे कई विकास-संबंधित विषय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जब उन्नत दृष्टिकोण से पर्यावरणीय स्थिरता पर विचार किया जाता है, तो जलवायु वित्त का महत्व तुरंत सामने आता है। हालांकि भारत का क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस बढ़ रहा है, फिर भी निर्बाध कम-कार्बन संक्रमण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। राष्ट्र की अधिकांश जलवायु कार्रवाई घरेलू बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी बजट द्वारा वित्त पोषित है। व्यापक रुझानों के अनुसार, जलवायु वित्त प्रवाह एक साथ आ रहे हैं।

जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विकासात्मक पहलों के साथ तालमेल बनाकर काम करने वाले महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाना अनिवार्य है। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन में मानव जाति को गंभीर रूप से खतरे में डालने की क्षमता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, दुनिया भर के देश धन और संसाधन जुटा रहे हैं। भारत ने अपने 2030 के एनडीसी में सुधार किया और कॉप 26 में 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य घोषित किया। मुख्य रूप से, भारत ने अगले दस वर्षों के दौरान अमीर देशों से जलवायु वित्तपोषण में 1 ट्रिलियन डॉलर की मांग की है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों और विवेकपूर्ण निवेश की आवश्यकता है ताकि उत्सर्जन को कम किया जा सके, पहले से महसूस किए जा रहे प्रभावों के अनुकूल ढलने को प्रोत्साहित किया जा सके और लचीलेपन को बढ़ाया जा सके।

कई विकासशील देशों की तरह, भारत के पास टिकाऊ ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए वित्तीय साधनों की कमी है, जो जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। अपने 2030 के जलवायु शमन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक खर्च करने होंगे। इसमें एक न्यायसंगत संक्रमण का खर्च शामिल नहीं है, और यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो संभवतः इसमें नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। वर्तमान में पहले से अनुमानित जलवायु वित्त पोषण आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत से भी कम भारत के ट्रैक किए गए जलवायु निवेशों द्वारा पूरा किया जाता है। 2015 और 2030 के बीच, अनुकूलन और लचीलेपन पर अतिरिक्त 1 ट्रिलियन डॉलर के व्यय की आवश्यकता है, या 2030 तक प्रति वर्ष 67 बिलियन डॉलर।

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष: अगस्त 2015 में भारत के उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। "एनएएफसीसी के तहत परियोजनाएं उन जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं जो एसएपीसी (राज्य कार्य योजना जलवायु परिवर्तन) के तहत जलवायु लचीलापन क्षेत्र और एनएपीसीसी (राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन) के तहत प्रासंगिक मिशन बनाती हैं। (नाबार्ड)"

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: प्राथमिकता क्षेत्र का वर्गीकरण 35 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋणों पर लागू होगा जो उधारकर्ताओं को पवन टरबाइन, माइक्रो-हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, सौर ऊर्जा संचालित जनरेटर, बायोमास-आधारित बिजली जनरेटर और गैर-पारंपरिक ऊर्जा-आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण और स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम जैसी परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं। (अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, 2023)

ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन बॉन्ड जारी करना:

- "ग्रीन डिपॉजिट एक प्रकार का सावधि जमा है जहां धन विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निर्धारित किया जाता है," जबकि "ग्रीन बॉन्ड एक संगठन द्वारा परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के उद्देश्य से जारी की गई ऋण प्रतिभूति है जो पर्यावरण और/या जलवायु में सकारात्मक योगदान देती है।"
- भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड यस बैंक द्वारा फरवरी 2015 में 1,000 करोड़ रुपये के 10-वर्षीय निर्गम के रूप में जारी किया गया था, जो लगभग दो बार ओवरसब्सक्राइब हुआ था, जिसकी आय सौर, पवन और बायोमास जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को निर्देशित की गई थी। यस बैंक ने अगस्त 2015 में एक और 315 करोड़ रुपये के 10-वर्षीय निर्गम के साथ इसका अनुसरण किया, जिसे पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा सब्सक्राइब किया गया था। (सेबी कॉन्सेप्ट पेपर)

सतत वित्त समूह: भारतीय रिजर्व बैंक के भीतर सतत वित्त समूह की स्थापना मई 2021 में जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को संबोधित करने और सतत वित्त में नियामक पहलों का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य पर्यावरण की दृष्टि से ठोस वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा देना और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण का समर्थन करना है। (आरबीआई 2022)

नेटवर्क फ़ॉर ग्रीनिंग ऑफ़ फ़ाइनेंशियल सिस्टम: एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के बीच एक संघ है जो हरित वित्त के स्केलिंग में तेज़ी लाने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में केंद्रीय बैंकों की भूमिका के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए काम करता है। आरबीआई 23 अप्रैल, 2021 को नेटवर्क फ़ॉर ग्रीनिंग ऑफ़ फ़ाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया। यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों को इस क्षेत्र में एक-दूसरे से साझा करने और सीखने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है।

जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली: जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों का मूल्यांकन करते समय, डेटा आवश्यक होता है। जलवायु परिवर्तन के जोखिम का आकलन करने के लिए उपलब्ध डेटा में कई प्रतिबंध और कमियां हैं। डेटा अंतराल को बंद करने और डेटासेट को मानकीकृत करने के लिए, आरबीआई ने आरबी-सीआरआईएस (जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली) के निर्माण की घोषणा की है, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय प्रभाव आकलन की तुलनात्मकता सुनिश्चित करेगा। कार्बन उत्सर्जन कारक डेटाबेस, संक्रमण जोखिम मूल्यांकन और भौतिक जोखिम मूल्यांकन डेटा सभी के आरबी-सीआरआईएस द्वारा कवर किए जाने की उम्मीद है।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड: ये केंद्र सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित हरित पहलों के लिए धन आवंटित करने के लिए जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 ने हरित अवसंरचनात्मक निवेश के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की, जो ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करेंगे, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों को कम करेंगे, जलवायु लचीलापन और/या अनुकूलन आदि को बढ़ावा देंगे। (केंद्रीय बजट, 2022-23)

जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई: 2011 में स्थापित, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत यह प्रमुख संस्थान, सभी जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण मामलों पर नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सभी प्रयासों से, यह कहा जा सकता है कि जलवायु स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है, जैसे शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य और अन्य, लेकिन यह सागर में एक बूंद के समान है। इस मुद्दे के संबंध में और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, और इस समस्या से निपटने के लिए प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मंचों, सरकारों तथा सार्वजनिक और निजी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए। इस विशाल, नीली, गोलाकार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए इन मुद्दों पर विचार करना समय की मांग है और राष्ट्रीय स्तर पर, 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए एनजीएफएस और एसजीएफ जैसी नीतियों और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जैसे उपकरणों के साथ-साथ हरित बजट जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए। ❑

(सह-लेखक, अभिषेक कुमार उपाध्याय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के वाणिज्य विभाग में शोधार्थी हैं)